ment, discussions have been held with State Governments, Development Authorities and larger Municipal Corporations on the subject in regard to areas where public-private partnerships can be considered and on modalities for involving the private sector in the provisions of municipal services. Since Local Self-Government is a State subject, a final decision regarding privatisation of municipal services has to be taken by the respective State Governments/Local Bodies.

महानगरों को वित्तीय सहायता

5183. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के चार महानगरों की प्रमुख शहरी समस्याओं को हल करने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने चार महानगरों के लिए केन्द्रीय सहायता कोष से कितनी धनराशि का आबंटन किया है;

(ग) बम्बई शहर के लिए बिजली, पानी, सड़क, आवास, परिवहन, सफाई इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता कोष से 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने के संबंध में सरकार से की गई मांग के बारे में मंत्रालय ने अब तक कौन से ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने गंदी बस्तियों के सुधार के संबंध में कोई योजना तैयार की है ताकि आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और उनका उत्थान किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) "शहरी विकास" राज्य विषय है इसलिए कस्बों तथा शहरों को विकास हेतु परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना धन से अथवा बाह्य सहायता से तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। विनिर्माण बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि जैसे बड़े महानगरों की व्यापार, परिवहन के क्षेत्र में भूमिका और योगदान और एक तरफ राजकोष में उनके अंशदान तथा दूसरी तरफ अवस्थापन संबंधी कमियों तथा स्टेट सेक्टर से सीमित वित्तीय सहायता को स्वीकारते हुए महानगरों को अवस्थापन विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई है। इस योजना में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर शहर शामिल हैं। इस योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संस्थागत वित्त के मध्य 25:25:50 की भागीदारी निर्धारित है। वर्ष 1993-94 के दौरान रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं। बम्बई 20.10 करोड़ रुपए, कलकत्ता 20.10 करोड़ रुपए, मद्रास 15.10 करोड़ रुपए, हैदराबाद 15.10 करोड़ रुपए तथा बंगलौर 0.10 करोड़ रुपए।

(घ) तथा (ङ) निर्धारित स्लमों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अंतर्गत मुहैया कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता प्राप्त शहरी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्लम सुधार अथवा स्लम बेहतरी परियोजना का एक घटक है और तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना में स्लम सुधार घटक पर परियोजना लागत 45.65 करोड़ रुपए है जबकि बी. यू. डी. पी. में यह लागत 21.60 करोड़ रुपए है।

सरदार सरोवर परियोजना से बिजली की उपलब्धता

5184. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार सरोवर अंतर-राज्यीय पन बिजली परियोजना से संबंधित कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश को कितनी बिजली उपलब्ध करायी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): सरदार सरोवर परियोजना के नहर मुख्य विद्युत घर पर कार्य दिसम्बर, 1995 तक